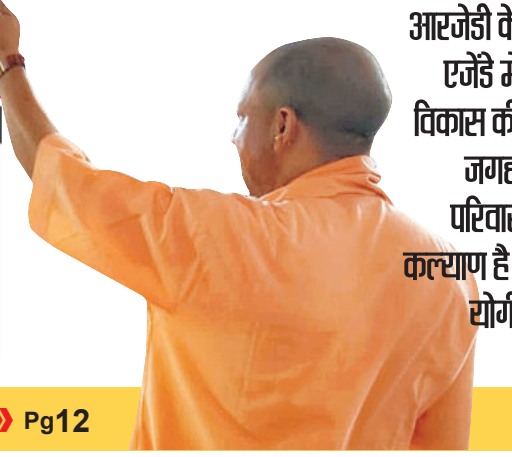


स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन



कानपुर, गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025
वर्ष: 02, अंक: 274, पृष्ठ: 8+4, मूल्य: ₹ 2/-

इनसाइड

कानपुर: नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई!... Pg03

Pg12

निशाने पर कोल्ड्रफ सहित दो और कफ सिरप मौत के सौदागरों पर शीघ्र कसेगा शिंकजा

रेस्पिफ्रेश टीआर व रीलाइफ सिरप की भी जांच के निर्देश

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया।

लखनऊ। यूपी में कफ सिरप निर्माताओं और बेचने वालों पर अभी और शिंकजा कसेगा। अभी तक की जांच और छापेमारी में कोल्ड्रफ तो नहीं मिला मगर उत्तर प्रदेश में अब दो और कफ सिरप की खोजबीन शुरू हो गई है। यह सिरप हैं, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ। कोल्ड्रफ के अलावा भारत में बने इन दोनों सिरप को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने खतरनाक बताया है। इसे लेकर चेतावनी जारी की है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. रोशन जैकब ने सभी जिलों को रेस्पिफ्रेश टीआर व रीलाइफ सिरप की भी जांच के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों देश के कई राज्यों में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड में आई और तत्काल प्रभाव से कोल्ड्रफ कफ सिरप बेचने पर रोक लगा दी गई थी।

प्रदेश में नकली दवाओं का बड़ा कारोबार है। इस खेल से जुड़े अंतरराज्यीय

गैंग की प्रदेश में गहरी जड़ें हैं। नामचीन कंपनियों के नाम से बनीं दवाएं और सिरप यहां बड़े पैमाने पर खपाए जा रहे हैं।

बीते दिनों में ताजनगरी आगरा में एक बड़ा मामला सामने आया था जबकि बीते मंगलवार को लखीमपुर खीरी में भी नारकोटिक्स विंग ने करीब 70 लाख रुपये की दवाएं पकड़ी थीं। राजस्थान व मध्य प्रदेश में हाल ही में कई बच्चों की मौत का कारण कोल्ड्रफ कफ सिरप को बताया गया है। इसी के चलते कफ सिरप को लेकर केंद्र ने यूपी सहित सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की। जिसमें पांच साल तक के बच्चों को कफ सिरप न देने और इससे बड़ों को चिकित्सक की सलाह पर ही देने को कहा गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कोल्ड्रफ के अलावा पिछले सालों में जिन कफ सिरप पर कार्रवाई हुई, उनके सहित तमाम कंपनियों के कफ सिरप

के सैंपल लिए गए हैं। इनकी संख्या तकरीबन 800 है। आयुक्त डा. जैकब के अनुसार लैब में इनकी जांच चल रही है। अब तक सामने आए दो दर्जन से अधिक नतीजों में कोई भी अनसेफ नहीं मिला है। अब डब्ल्यूएचओ के रीलाइफ व रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप को खतरनाक बताए जाने के बाद प्रदेश में



इनकी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर की ओर से इस संबंध में सभी औषधि निरीक्षकों को जांच के लिए कहा गया है।

व्हाट्सएप पर दें सूचना: आयुक्त

जानकारी के अनुसार आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. रोशन जैकब ने प्रदेश में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार प्रवर्तन अभियान जारी किया। उन्होंने नकली दवाओं के निर्माण या

तीन सिरप के खिलाफ
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी

डब्ल्यूएचओ ने बीते सोमवार को भारत में तीन मिलावटी कफ सिरप-कोल्ड्रफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ को लेकर चेतावनी जारी की थी। डब्ल्यूएचओ ने दुनियाभर के देशों से कहा है कि अगर उनके यहां ये दवाएं मिल रही हैं तो इसकी सूचना तुरंत संगठन को दें। संगठन ने डॉक्टरों को भी सलाह दी है कि वे इन मिलावटी दवाओं का पता लगने तथा प्रतिकूल प्रभाव की किसी भी घटना की सूचना अपने राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों या नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर को दें।

आयुक्त छापेमारी में हुआ था
अवैध दवाओं का पर्दाफाश

आपको बता दें कि लखनऊ में नॉरकोटिक्स औषधियों और कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध व्यापार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने बड़ी कार्रवाई की थी। आयुक्त रोशन जैकब के नेतृत्व में बीते रविवार को एफएसडीए (औषधि) की टीम ने लखनऊ, सीतापुर और रायबरेली में एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध दवा कारोबार का पर्दाफाश किया था।

भंडारण की सूचना के लिए व्हाट्सअप नम्बर-(8756128434) जारी किया है।

उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अधोमानक, नकली, मिथ्याछाप एवं अपमिश्रित औषधियों के निर्माण, भण्डारण व विक्रय के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, जिससे जनस्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना हो, तो ऐसी गोपनीय सूचना इस नंबर पर दे सकते हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

वकील भी हुए खिलाफ

एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश पर चलेगा केस!

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश करने वाले राकेश किशोर की मुठिक्के बढ़ गई हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने गुरुवार को जूताकांड में राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाने की अपनी मंजूरी दे दी है। भगवान विष्णु पर सीजेआई गवई की टिप्पणी से नाराज राकेश किशोर ने छह अक्टूबर को उन पर भरी कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश

की थी। हालांकि, बाद में सीजेआई ने उन्हें माफ करते हुए कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था।

अटॉर्नी जनरल द्वारा अवमानना की मंजूरी दिए जाने की बात की जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब दी, जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने इस मामले को उठाया। कोर्ट की अवमानना

क नियम सेक्शन 15 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इसकी कार्रवाई शुरू किए जाने से पहले अटॉर्नी जनरल की मंजूरी की जरूरत होती है। सीजेआई गवई पर जूता फेंकने के मामले में अटॉर्नी जनरल की ओर से यह मंजूरी दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी और एजी वेंकटरमणी को पत्र लिखा था। विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को कल लिस्ट करने की मांग की।



उन्होंने लिखा, जूता फेंकने के मामले को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राकेश किशोर को जूता फेंकने पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने अटॉर्नी जनरल से मंजूरी मांगी थी और इसे कल लिस्ट किया जा सकता है। सोशल मीडिया इस मामले में पागल हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस

मामले को गंभीर बताया है।

उन्होंने कहा, राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए एजी द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। संस्था की ईमानदारी दांव पर है। कुछ कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि, इतना सब सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस घटना को जाने देना ही सबसे बेहतर होगा। मेहता और सिंह ने अदालत से सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट करने पर रोक से संबंधी आदेश पारित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि हर तरह की अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। पीठ ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार दूसरों की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता है। हालांकि, कोर्ट ने मामले की कल मामले की सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया है। जस्टिस कांत ने कहा, देखते हैं एक हफ्ते में क्या होता है और भी बिकने वाली चीजें पढ़ेंगे। वहीं, जस्टिस बागची ने कहा कि

नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई...!

चार मेडिकल स्टोरों की बिक्री पर रोक, शहर में चल रही थी नशे की सप्लाई चेन

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शासन के आदेश पर ड्रग विभाग की टीम ने शहर में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक साथ कई इलाकों में छापेमारी कर चार दवा दुकानों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन मेडिकल स्टोरों से बड़ी मात्रा में कोडिन सिरप, एल्प्रोजोलम टैबलेट और पेन-किलर जैसी नशे में प्रयोग होने वाली दवाएं बरामद की गई हैं।

ड्रग इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह ने बताया कि बिरहाना रोड, लालबंगला और कल्याणपुर क्षेत्रों में हुई छापेमारी के दौरान दुकानों के संचालक पिछले दो वर्षों के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसे में विभाग ने बिक्री पर रोक



लगाते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बुधवार को ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान और ओमपाल सिंह की अगुवाई

में बिरहाना रोड स्थित अग्रवाल ब्रदर्स और शांति ट्रेडर्स पर छापेमारी की गई। अग्रवाल ब्रदर्स में नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं इसी तरह लालबंगला स्थित आरएस हेल्थकेयर और केशवपुरम स्थित एसएस हेल्थकेयर पर भी कार्रवाई हुई, जहां दवाओं के रिकार्ड गायब पाए गए। ड्रग विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस, फर्जी बिलिंग या संदिग्ध दवाओं की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोरों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐसी दवाएं सीधे तौर पर युवाओं के जीवन को संकट में डाल रही हैं और शहर में नशे की जड़ें गहरी कर रही हैं।

आरटीई में एडमिशन न देने पर सख्त कार्रवाई शुरू

» डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक और एस्कॉर्ट वर्ल्ड स्कूल का यू-डॉयस नम्बर निलम्बित

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) का पालन न करने पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। शहर के दो विद्यालयों, डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल गोविन्द नगर और एस्कॉर्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम कल्याणपुर का यू-डॉयस नम्बर निलम्बित कर दिया गया है। दोनों विद्यालयों ने अभी तक इस शैक्षणिक वर्ष के लिए आरटीई अधिनियम के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के कई बच्चों को आवंटन होने के बावजूद दाखला नहीं दिया।

इन बच्चों के अभिभावक जनता दर्शन में लगातार अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी को दाखला कराने के निर्देश दिए। इसके बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने कोई रुचि नहीं दिखाई।

डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में नियति मिश्रा और प्रनय सोनी को क्रमशः 30 दिसम्बर 2024 और 29 जनवरी 2025 को प्रवेश आवंटित हुआ था। कई बार नोटिस देने और 8 व 9 अक्टूबर को अंतिम चेतावनी देने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने साफ कह दिया कि आरटीई के तहत कोई प्रवेश नहीं लिया जाएगा।

इसी प्रकार एस्कॉर्ट वर्ल्ड स्कूल में दिव्यम श्रीवास्तव, मानवेन्द्र और मोहम्मद रेयान अखतर को आरटीई के तहत दाखला आवंटित हुआ था। विद्यालय ने तीनों बच्चों को प्रवेश नहीं दिया। 19 जून, 11 जुलाई और 19 सितम्बर 2025 को विभाग ने बार-बार नोटिस जारी किए, खंड शिक्षा अधिकारी शास्त्री नगर ने कई बार विद्यालय पहुंचकर प्रयास किया, लेकिन प्रधानाचार्या ने न तो दाखला लिया और न ही कोई जवाब दिया।

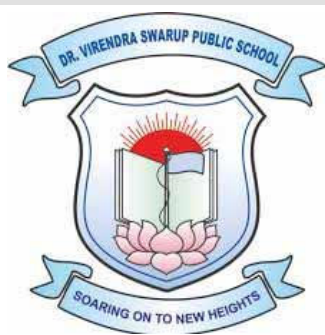
दोनों विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवंटित बच्चों का प्रवेश कराने में समुचित

यू-डॉयस निलम्बन के बाद क्या होता है

डॉ. सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी विद्यालय का यू-डॉयस नम्बर उसकी शैक्षणिक पहचान है। इसके निलम्बित होते ही विद्यालय विभागीय पोर्टलों पर अपडेट नहीं हो पाता और सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाता है। नए विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण और दाखला रुक जाता है तथा शिक्षा विभाग मान्यता निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।

इस वर्ष 4663 बच्चों का आरटीई के तहत हो चुका है दाखिला

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में इस शैक्षणिक सत्र में जिले के 712 विद्यालयों में कुल 4663 बच्चों का प्रवेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत कराया जा चुका है। वर्तमान में जिले की विभिन्न कक्षाओं में 16 हजार से अधिक छात्र-छात्राएँ इस अधिनियम का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष कई विद्यालयों ने विशेष सक्रियता दिखाते हुए आवंटित बच्चों का शत-प्रतिशत दाखला सुनिश्चित किया है। इनमें शीलिंग हाउस, ओंकारेश्वर विद्या मंदिर, बीएनएसडी शिक्षा निकेतन, मरियमपुर पब्लिक स्कूल और स्वराज इंडिया स्कूल प्रमुख हैं। इन विद्यालयों ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आरटीई के प्रावधानों के अनुरूप सभी बच्चों का प्रवेश किया है।



रुचि नहीं दिखा रहे हैं। डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में इस वर्ष आरटीई के तहत 30 बच्चों को दाखले के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन विद्यालय ने केवल 12 बच्चों को ही प्रवेश दिया। इसी प्रकार एस्कॉर्ट वर्ल्ड स्कूल में 35 बच्चों का आवंटन हुआ था, जबकि इनमें से मात्र 7 बच्चों का ही दाखला लिया गया जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध है। इन स्कूलों में शेष बच्चों का

प्रवेश न होने से अभिभावक लगातार परेशान हैं और डीएम सहित विभिन्न जन प्रतिनिधियों से मिलकर लगातार एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं।

अधिकारियों की संस्तुति के बाद दोनों विद्यालयों के यू-डॉयस नम्बर निलम्बित कर दिए गए हैं। डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल का यू-डॉयस नम्बर 09341103909 और एस्कॉर्ट वर्ल्ड स्कूल का यू-डॉयस नम्बर 09341110927 निलम्बन की श्रेणी में आ गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य समाज के अलाभित और कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह केवल कानूनी दायित्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों ने अभी तक आरटीई के तहत आवंटित बच्चों का दाखला नहीं लिया है, वे आगे आकर इस जिम्मेदारी को निभाएँ। इससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा और विद्यालय की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।

मध्याह्न भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति सीएम डैशबोर्ड हटाया गया

» सीएम डैशबोर्ड पर जिलों की रैंकिंग से हटा दिया है



» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मध्याह्न भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति से जुड़े सीएम डैशबोर्ड पर जिलों की रैंकिंग से हटा दिया है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने विभागीय योजनाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति को भौतिक एवं वित्तीय उपभोग के आंकड़ों से पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं होने के कारण जिलों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते

हुए मध्याह्न भोजन (एमडीएम) तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति संबंधी योजनाओं के तहत रैंकिंग नहीं करने तथा इसे सीएम डैश बोर्ड ने हटाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभाग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए एमडीएम तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रोजेक्ट को पलैगशिप प्रोजेक्ट से अलग करते हुए जिलों की रैंकिंग से हटाने के निर्देश जारी कर दिया है।

नवागंतुक नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय-घाट से लेकर शौचालय तक औचक निरीक्षण

दीपावली से पूर्व शहर की सफाई व विकास कार्यों को लेकर नगर आयुक्त सख्त

» इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय (आईएस) ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था, जनसुविधाओं और विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाट, सामुदायिक शौचालयों सहित कई स्थलों की सफाई स्थिति देखी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहर में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए।

सबसे पहले नगर आयुक्त सरसैया घाट (जोन-1) पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूजा-अर्चना और स्नान स्थलों पर उच्च स्तर की सफाई व्यवस्था हर समय सुनिश्चित की जाए। घाट परिसर में पर्याप्त डस्टबिन, नियमित कचरा उठान और शाम के समय सुपरवाइजर की उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए इसके बाद उन्होंने मोतीझील (जोन-4) स्थित सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। शौचालय की स्वच्छता, जलापूर्ति और प्रकाश व्यवस्था की जांच करते हुए उन्होंने केयरटेकर को निर्देशित किया कि शौचालय प्रतिदिन प्रातः 4 बजे तक खुल जाए, ताकि नागरिकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी सामुदायिक शौचालयों में दैनिक सफाई, कीटाणुनाशक छिड़काव और जल निकासी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता व



जनसुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर क्षेत्रीय अधिकारी विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अपराह्न 4 बजे नगर निगम सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों, कूड़ा उठान, डोर-टू-डोर कलेक्शन

और निस्तारण व्यवस्था की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि जन शिकायतों का शीघ्र निस्तारण और नियमित मॉनिटरिंग से गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित किया जाए।

सायं 5 बजे अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने सभी विकास कार्यों को समयसीमा और तकनीकी मानकों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की

गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और वे स्वयं समय-समय पर औचक निरीक्षण करते रहेंगे।

नगर आयुक्त उपाध्याय ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है, और इसके लिए सभी अधिकारियों को पूरी निष्ठा और तत्परता से कार्य करना होगा।

दीपावली और छठ पर लोगों की बह्ले-बह्ले... चलेंगी अतिरिक्त बसें, चालक-परिचालकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दीपावली, भैयादूज और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक प्रोत्साहन अवधि घोषित किया गया है, प्रोत्साहन अवधि में कार्यरत चालकों, परिचालकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है, जिसमें इन्हें इस अवधि में कार्य करने पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

यह जानकारी परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को दी, उन्होंने कहा कि पर्वों पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर सहित प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और इटावा के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दौरान पूर्वांचल के लाखों लोगों का घर वापसी सफर बिना किसी असुविधा के पूरा हो, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में कार्यरत चालकों, परिचालकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है।



कर्मचारियों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि जो चालक-परिचालक 12 दिन ड्यूटी करते हुए औसतन 300 किमी प्रतिदिन का संचालन करेंगे, उन्हें 400 रूपए प्रतिदिन की दर से 4800 रूपए दिए जाएंगे। यदि कोई कर्मी 13 दिन लगातार ड्यूटी करता है और तय मानक पूरा करता है, तो उसे 450 रूपए प्रतिदिन की दर से 5850 रूपए मिलेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अनुबंधित चालकों-परिचालकों को मानक से अधिक चलने पर 55 पैसे प्रति किमी अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। कार्यशाला

कर्मचारियों को 13 दिन लगातार ड्यूटी पर 2500 रूपए और 12 दिन पर 2100 रूपए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उत्कृष्ट कार्य के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को 10 हजार रूपए, सेवा प्रबंधकों को पांच हजार रूपए और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को बसों के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा अनिवार्य परिवहन मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रोत्साहन अवधि में प्रवर्तन दल लगातार निरीक्षण करें और सभी चालकों-परिचालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाए, ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके।

केस्को ठेकेदार की लापरवाही से फूटी पानी की लाइन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर कृष्णा नगर वार्ड नंबर 24 के कृष्णापुरम इलाके में केस्को ठेकेदार की लापरवाही के चलते बीते पांच दिनों से सैकड़ों लीटर पानी सड़कों पर बह रहा था। जानकारी के अनुसार, केस्को के ठेकेदार ने बिजली के नए खंभे लगाने के दौरान एक खंभा सीधे पानी की लाइन पर गाड़ दिया था। इसके चलते लाइन फट गई और लगातार पानी रिसता रहा स्थानीय निवासी एवं पूर्व पार्षद मदन लाल भाटिया ने बताया कि बार-बार शिकायत के बावजूद न तो जलकल विभाग ने ध्यान दिया और न ही केस्को अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों की उदासीनता से न

केवल पानी की बर्बादी हुई बल्कि सड़क पर गंदा पानी भर जाने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। आज सुबह जब श्री भाटिया ने जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता जेपी गुप्ता और केस्को अधिकारियों को मामले से अवगत कराया, तब जाकर खंभा हटाया गया और लीकेज की मरम्मत का कार्य शुरू हो सका। मदन लाल भाटिया ने कहा कि यह घटना विभागीय समन्वय की कमी और जिम्मेदारों की लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने मांग की कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सभी जमा रसीदें हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेब साइट पर अपलोड जरूर कर दें।



जहां लिखी जाती हैं एफआईआर, वहां तैयार हुआ भावनात्मक माहौल थाने में फिल्मी कलाइमेक्स और जुड़ गए टूटे हुए दिल

अरौल थाने में गुस्से से तमतमाया चेहरा लेकर आई पत्नी, मुस्कान लेकर लौटी

मिशन शक्ति के तहत टूटे दिलों ने फिर बांधा प्यार का बंधन

» रिजवान कुरैशी, स्वराज इंडिया न्यूज़।

अरौल/बिल्हौर (कानपुर)। एक शिकायत... दो बिछड़े दिल और थाने की चौखट। बुधवार को अरौल थाना परिसर में एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जो किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। क्षेत्र के समियापुर गांव की निवासी रेखा देवी अपने पति पंकज कुमार से मनमुटाव के चलते अलग रह रही थीं। शादी के वक्त सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाले दोनों पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि रिश्ता टूटने की कगार पर था।

दरअसल, बुधवार को रेखा देवी अपनी शिकायत लेकर थाने के मिशन शक्ति केंद्र



थाने में खुशियों का माहौल

पुलिस ने थाने में ही दोनों के लिए फूलों की माला मंगाई। पति-पत्नी ने एक-दूसरे को माला पहनाई तो थाना परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। पुलिस ने दोनों को मिठाई खिलाई और विदा किया। तमतमाते चेहरे लेकर आई पत्नी मुस्कान लेकर लौट गई।

पहुँचीं। थानेदार जनार्दन सिंह यादव के निर्देशन में केंद्र प्रभारी उपनिरीक्षक प्रीतांजलि यादव और महिला आरक्षी सोनम व रश्मि ने उनकी पूरी बात सुनी। इसके बाद पंकज कुमार को थाने बुलाया गया। थोड़ी ही देर में केंद्र की टीम ने दोनों को बैठाकर समझाया

कि विवाह केवल कानूनी रिश्ता नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार की नींव पर टिकता है। बातचीत और समझाने के तरीके ने ऐसा असर दिखाया कि पंकज भावुक हो गए और रेखा देवी की आंखें भी गीली हो गईं। फिर दोनों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया।

प्रेरणा बन गई पहल

अरौल थाना परिसर में मिशन शक्ति के तहत टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने का यह प्रयास समाज में सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। बिल्हौर सर्किल के अरौल पुलिस स्टेशन ने इस सराहनीय पहल से साबित कर दिया कि थाने सिर्फ मुकदमे दर्ज करने की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का भी स्थान बन सकते हैं।

हाथों की स्वच्छता से ही स्वस्थ समाज का निर्माण: तहसीलदार



» वैश्विक हैंड वाश दिवस पर बच्चों ने सीखे हाथ धोने के आठ आसान स्टेप।

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। वैश्विक हैंड वाश दिवस के अवसर पर बीते बुधवार को प्राथमिक विद्यालय गोहलियापुर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि तहसीलदार अनुभव चंद्रा ने बच्चों को हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हाथ न केवल बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि

एक स्वस्थ समाज की नींव रखते हैं। तहसीलदार ने बच्चों को हाथ धोने के आठ आसान स्टेप सिखाए और बताया कि साबुन से हाथ धोते समय हथेलियों, उंगलियों, अंगूठे, नाखूनों और कलाई की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने बच्चों से अपील की कि स्वच्छ हाथ, स्वस्थ जीवन का संदेश हर घर तक पहुंचाएं। इसके बाद उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण भी किया और स्वच्छता व्यवस्था की सराहना की। कार्यक्रम में शिक्षिका आशा कटियार, भावना त्रिवेदी, सिंपल कटियार आदि सहित पूरा स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा।

मिलावटखोरों पर शिकंजा: चौबेपुर में 52 क्विंटल मिलावटी खोया जब्त

त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा टीम ने की बड़ी कार्रवाई



» जेसीबी से नष्ट कराया खोया, मिठाई कारोबारियों के खिलाफ जांच जारी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो।

चौबेपुर, बिल्हौर (कानपुर)। त्योहारों के सीजन में खाने-पीने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार शाम चौबेपुर में हाईवे पर मरियानी गांव के पास चार गाड़ियों से लाया जा रहा 52 क्विंटल मिलावटी खोया जब्त किया गया।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा कार्यालय के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह खोया मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। इसे जेसीबी से खोदकर गड्ढे में डाल मिट्टी में मिलाकर नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने कहा कि नमूने जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट आने के बाद खोया कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम का यह अभियान न केवल खोये तक सीमित है, बल्कि शहर और आसपास के जिलों में पनीर, दूध, घी, मिठाई, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, खाद्य

तेल, रंगीन मीठे खिलौने और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। टीम समय-समय पर निर्माण इकाइयों, भंडारण स्थलों, कोल्ड स्टोरेज और मंडियों का निरीक्षण करती रहेगी।

धूमधाम से मनाई एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती

बिल्हौर (कानपुर)। पद्मवी क्लासेज में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों ने कलाम के जीवन और उनके संघर्षों से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान संचालक विशाल चतुर्वेदी, मनोज चतुर्वेदी, सारिका और रजनी ने कलाम साहब के योगदानों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कृष्णा, राज, शिवम, अंश, अर्पित, शिवांशु, अभिराज, लक्ष्य, दीपांशु, सौम्या, राजम, तुंबा, अंशी, तलत आदि बच्चों ने अपने विचार साझा किए। सभी ने डॉ. कलाम के आदर्शों पर चलने और देश के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया।

सम्पादकीय

आवश्यक सुधारों से ही आर्थिकी को गति

जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ पर पश्चिमी शक्तियों के मंसूबों के अनुरूप सुर में सुर मिलाने का आक्षेप लगता रहा है, यदि वह अब भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर दर्शाए तो इसे हम अपनी आर्थिकी की ताकत के रूप में देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आईएमएफ ने वर्ष 2025-26 के लिये भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। इस नवीनतम अपडेट से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में देश की स्थिति और मजबूत हुई है। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह संशोधन लचीली घरेलू खपत, मजबूत सेवा निर्यात और स्थिर सार्वजनिक निवेश के दृष्टिगत किया है। यह सुखद ही कहा जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने और भारी-भरकम टैरिफ का कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। लेकिन इस आशावाद के बावजूद हमें अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य की वास्तविकता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिसके मूल में तमाम व्यापारिक व्यवधान, अमेरिकी टैरिफ वृद्धि और सख्त वित्तीय स्थितियों जैसे घटक भी शामिल हो सकते हैं। जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कहीं न कहीं भारत की आर्थिक गति को प्रभावित कर सकते हैं। निर्विवाद रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में आईएमएफ का भरोसा, मजबूत भारतीय घरेलू

बाजार, राजकोषीय अनुशासन और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के उद्देश्य से किए गए सुधारात्मक उपायों के चलते जगा है। वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे पर खर्च, डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहन और बेहतर कर संग्रह ने व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत ही किया है। हालांकि निर्यात, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र, संरक्षणवादी नीतियों और कमजोर वैश्विक मांग के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर चीन की मंदी और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्संतुलन के साथ, भारत के सामने चुनौती और अवसर दोनों ही मौजूद हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाते हुए आत्मनिर्भरता की राह में कदम आगे बढ़ाए। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौती को महसूस करते हुए 'मेक इन इंडिया' की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास एक आंदोलन के रूप में किया है। दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत विनिर्माण पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकारकीप्राथमिकता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सेमीकंडक्टर और हरित प्रौद्योगिकियों के लिये लक्षित प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना है।

आरटीआई कानून को प्रभावकारी बनाने की जरूरत

ज्योति मल्होत्रा

आरटीआई कानून शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है जो लोकतंत्र की जरूरत भी है। आवेदन करने में बाधाओं के बावजूद अब वेबसाइट लिंक मुहैया होना सकारात्मक पहलू है। बेशक कुछ संशोधनों से सूचना आयोगों पर असर पड़ा है। आरटीआई कानून शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है जो लोकतंत्र की जरूरत भी है। आवेदन करने में बाधाओं के बावजूद अब वेबसाइट लिंक मुहैया होना सकारात्मक पहलू है। बेशक कुछ संशोधनों से सूचना आयोगों पर असर पड़ा है। पूरे 20 साल पुराने इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए लोगों को आगे आना होगा। भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त होने के नाते मुझे राजस्थान स्थित ब्यावर में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हुए समारोह में आमंत्रित किया गया, वह शहर जहां 1996 में इस प्रकार का कानून बनाए जाने के समर्थन में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था।

अपने संबोधन की शुरुआत मैंने गुरुदत्त की क्लासिक फिल्म 'कागज के फूल' के गीत की पंक्तियों से की— 'वक्त ने किया क्या हसीं सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम...' अब जबकि 2005 में आए इस अधिनियम की सालगिरह मनाई जा रही है, इसको लेकर गर्मागर्म बहसें भी चली हुई हैं, अक्सर भावनात्मक, यह क्या फायदे लेकर आया और क्या चुनौतियां भी। कहा जा सकता है कि 2014 के राष्ट्रीय चुनावों में यह उसी सरकार को मुश्किल में डालने के कारणों में से एक रहा, जिसने इस अधिनियम को लागू किया था। अगली सरकार ने घोषित तौर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत को बरकरार रखने की बात कही और प्रशासन एवं सरकार की पहचान अलग रखने का प्रयास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के अपने चुनाव अभियान में 'पारदर्शिता अधिकतम और प्रशासनिक अड़ंगे न्यूनतम' रखने का वादा किया था— 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देकर प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ाने का वादा फिर भी, जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने हाल ही में ब्यावर में आयोजित एक आरटीआई मेले में अपने संबोधन में उल्लेख किया है, कानून में संशोधन और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए बनाए गए नए कानून के पारित होने के कारण सूचना आयुक्तों का अधिकार क्षेत्र घटा है और यह सूचना आयोगों की स्वतंत्रता में भी हास करने वाला है। आगे, आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में भी एक संशोधन किया गया है, जिसमें



सार्वजनिक हित स्थापित होने पर निजी मानी जाने वाली जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति थी। इसलिए, यह अधिनियम शासन की प्रकृति के संदर्भ में परिवर्तनकारी रहा। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि लोकतंत्र में सरकार का सार तत्व पारदर्शिता है, ताकि प्रत्येक अंग-कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका- नागरिक के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन जहां तक भारत में नौकरशाही की मानसिकता का प्रश्न है, 'माई-बाप' वाली सामंती सोच गणतंत्र के जन्म के बाद भी लंबे समय तक कायम है। सूचना का अधिकार अधिनियम घोषित करता है कि लोकतंत्र के लिए एक जागरूक नागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता होना आवश्यक है, जो इसके संचालन के लिए तो अत्यंत आवश्यक है साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, सरकारों एवं उनके तंत्रों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए भी जरूरी है। इस प्रकार, यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को शासन में प्रमुख भागीदार बनाने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कानून शासन को अत्यधिक सुदृढ़ बनाने में एक माध्यम है। आरटीआई अधिनियम को लेकर जागरूकता स्तर, अपने प्रारंभिक चरण में किसी भी अन्य कानून के बारे में जागरूकता की तुलना में काफी ऊपर था। सर्व में भाग लेने वाले 40 प्रतिशत से अधिक शहरी उत्तरदाताओं को इस अधिनियम के बारे में जानकारी थी, हालांकि ग्रामीण उत्तरदाताओं में यह आंकड़ा 20 फीसदी से भी कम था। ग्रामीण भारत में जागरूकता के स्रोत में - समाचार पत्र (35 प्रतिशत), टेलीविजन एवं रेडियो, दोस्त-रिश्तेदार (प्रत्येक 10 प्रतिशत), और एनजीओ (5 प्रतिशत) थे। शहरी क्षेत्र के लोगों में सजगता का मुख्य स्रोत समाचार पत्र (30 प्रतिशत), एनजीओ (20 प्रतिशत), टीवी (20 प्रतिशत) दोस्त और रिश्तेदार (10 प्रतिशत) था। नकारात्मक पहलू यह पाया गया कि प्रशासनिक अड़ंगे आवेदन दाखिल करने में अड़ंगा डालती रहीं। कि देश भर में अधिनियम को लागू करने के लिए आरटीआई नियमों के 114 अलग-अलग सेट थे और ऐसी कोई एक जगह नहीं थी।

पटाखों पर राजनीति के बजाय तार्किक समाधान निकालें

प्रदूषण को लेकर

ज्वाला सिंह दास

दिल्ली में दिवाली आते ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद बिज्री जारी है, जिससे आस्था, प्रशासन और पर्यावरण के बीच टकराव गह्रता जा रहा है। बीते दशक से दिल्ली में दिवाली के आसपास प्रदूषण की स्थिति खतरनाक हो जाती है और कोर्ट का मानना है कि पटाखों से प्रदूषण और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन इस प्रकरण की अहम बात यह है कि पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद बिज्री में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि प्रशासन की नाक के नीचे दुकानदार धड़ले से पटाखे बेचते हैं और लोग जमकर खरीदते भी हैं। बीते 7 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ग्रीन पटाखों की अनुमति लेगी। वर्ष 2019 से दिल्ली में सभी पटाखों पर बैन है और मुख्यमंत्री ने जनभावना को देखते हुए सीमित ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत मांगी थी।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पटाखों से प्रतिबंध हटाता है तो वह ऐसे सभी कदम उठाने को तैयार है, जिनसे निर्देशों का पूरी तरह पालन हो सके। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध हटा लिया जाता है तो हम अदालत के आदेश के आलोक में आवश्यक कदम उठाने के लिए तुरंत एक बैठक करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश का पालन हो। सरकार जिन पटाखों की पैरवी कर रही है, उनके विषय में यह बताया जाता है कि ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों की तुलना में 30 प्रतिशत कम प्रदूषण होता है। लेकिन कई वर्षों से पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो इसके लिए कोई ठोस काम कर पाई थी और न ही जागरूकता फैला पाई थी। इस बार बारी भारतीय जनता पार्टी की है, जिसे इस कसौटी पर खरा उतरना बाकी है। आम आदमी पार्टी के समय में बीजेपी के कई बड़े नेता इस मामले को लेकर केजरीवाल को घेरते थे और कहते थे कि पटाखों पर



बैन लगाना हिंदुत्व पर प्रहार है, हालांकि आदेश हर बार कोर्ट का ही होता था और अब भी कोर्ट का ही है। अब यह देखना बाकी है कि दिल्ली सरकार कितनी सक्रियता दिखाती है और किस तरह का समाधान निकालती है। दरअसल, हम प्रदूषण को लेकर आज तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि इसकी असली वजह क्या है। इस मामले को लेकर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। कुछ कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में प्रदूषण अपने आप बढ़ जाता है। बीते लगभग दो दशकों में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि दिल्ली से सटे हर कोने में जितनी हरियाली थी, वहां अब बड़ी-बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। जैसे गाजियाबाद से

सटे राज नगर में लाखों प्लैट बन चुके हैं। दूसरी ओर गुरुग्राम में जितनी हरियाली थी, आज वहां एक-एक इंच जमीन किसानों ने बेच दी और वहां भी लाखों प्लैट बन चुके हैं। बल्कि एशिया के सबसे महंगे प्लैट वहां बिकने लगे हैं। वहीं तीसरी ओर लोनी बॉर्डर और चौथी ओर फरीदाबाद में भी यही स्थिति है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि पराली जलाना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, क्योंकि इससे हवा में हानिकारक गैसों और कण फैलते हैं, जैसे मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। यह धुंध का निर्माण करता है, जो शहर की वायु गुणवत्ता को खराब करता है। पराली जलाने के कारण सर्दियों के महीनों में प्रदूषण का स्तर विशेष रूप से गंभीर हो जाता है, क्योंकि धीमी हवाएं इन प्रदूषकों को शहर के ऊपर फंसा देती हैं। रोमांस के राग-रंग बदल गई सोने की ऊंचाई दिल्ली-एनसीआर में हर रोज सैकड़ों नए वाहन खरीदे जाते हैं, अर्थात् राजधानी में अपनी क्षमता से अधिक वाहन हो चुके हैं, जो प्रदूषण बढ़ने का एक और

बड़ा कारण है। पटाखों को लेकर कोर्ट की सबसे जटिल समस्या यह है कि दीपावली सर्दी के मौसम में आती है, जब दिल्ली में प्रदूषण पहले से ही बहुत अधिक होता है। कोर्ट का मानना है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण और भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद पटाखों की बिक्री और खरीद में कोई कमी देखने को नहीं मिलती। पटाखों पर प्रतिबंध को कुछ लोग अपनी आस्था पर चोट मानते हैं, जिसको लेकर कई हिंदूवादी संगठनों और नेताओं के बयान हर वर्ष देखने और सुनने को मिलते हैं। यह बात तय है कि दिवाली हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इस पर्व पर पटाखे न जलाकर त्योहार अधूरा लगता है। जब से सनातन परंपरा का उदय हुआ है, तब से यह प्रथा चली आ रही है, और उसे निभाए बिना त्योहार पूरा नहीं लगता। सवाल यही है कि दिल्ली में इसका समाधान कैसे संभव है, क्योंकि हर वर्ष यही स्थिति दोहराई जाती है, जो त्योहार के उत्साही लोगों में कूटा पैदा कर रही है।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जयंती पर बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर बी.एन.एस.डी. शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, बेनाझाबर में बुधवार को एक भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रो. सुदर्शन नारायणन (सतत ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग, आई.आई.टी. कानपुर) के आगमन, दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण के साथ हुआ। विद्यालय की उप-प्रधानाचार्या मंजूबाला श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, जबकि कक्षा 12 की कनिष्ठ सिंह और अपर्णा पांडेय ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

मुख्य अतिथि प्रो. नारायणन ने विद्यार्थियों को विज्ञान और नवाचार के महत्व से अवगत कराया और कहा कि देश की प्रगति विज्ञान की सोच और युवाओं के नवाचार पर निर्भर है। उन्होंने विद्यार्थियों के बनाए मॉडलों का अवलोकन कर उनकी रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रशंसा की।

विद्यार्थियों की प्रतिभा ने बटोरा सबका ध्यान



प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अनेक नवीन और पर्यावरण अनुकूल मॉडल प्रस्तुत किए। लोक मिश्रा (कक्षा 11) ने ऑक्सीमेकर मॉडल बनाकर वायु प्रदूषण कम करने की तकनीक दिखाई।

आदित्य सिंह (कक्षा 11) ने बिना गैस वाला रेफ्रिजरेटर तैयार किया।

आदित्य पांडे (कक्षा 11) ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिजली को पुनः उपयोग में लाने की तकनीक दिखाई।

सांची (कक्षा 4) और धार्मिक गुप्ता ने वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट पर प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत किया। रुद्रिका गुप्ता (कक्षा 5) ने रोबोटिक हैंड, सिमरन साहू (कक्षा 5) ने वॉटर



प्युरीफायर, अनय सिंह ने एआई प्रेजेंटेशन के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता समझाई, वहीं अर्पित तिवारी ने सोलर सिस्टम का आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किया।

मुख्य अतिथि ने सभी विद्यार्थियों के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं में छिपी वैज्ञानिक

जिज्ञासा ही भारत को आत्मनिर्भर और नवाचारशील बनाएगी।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य बृजमोहन कुमार सिंह, शिक्षकगण, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। सभी ने प्रदर्शनी की सफलता पर विद्यार्थियों को बधाई दी।

मुआवजे की रकम के झगड़े में भाई ने भाई को गोली मारी

» जमीन अधिग्रहण के पैसों को लेकर उपजा विवाद, छोटे भाई की हालत

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बितूर थाना क्षेत्र के बनी गांव में बुधवार देर रात रिश्तों का खून से रंगा एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। यहां बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। मुआवजे की रकम को लेकर चले आ रहे विवाद ने भाईचारे को दुश्मनी में बदल दिया। घायल छोटे भाई टोनी तिवारी (25) को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी बड़ा भाई शिवम तिवारी अपने पिता रामचंद्र तिवारी उर्फ सत्तारे से नाराज था। पिता ने अपनी मर्जी से शादी करने पर शिवम को बेदखल कर दिया था। रिंग रोड अधिग्रहण में मिले 9 लाख रुपये के मुआवजे को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। पिता रामचंद्र केवल छोटे बेटे टोनी की



आर्थिक मदद करते थे, जिससे शिवम के अंदर खूनस पनप गई। बुधवार रात करीब 11-30 बजे टोनी मोहल्ले के जगदीश पासी के घर के पास से गुजर रहा था, तभी शिवम ने 315 बोर का तमंचा निकालकर उस पर गोली चला दी। गोली टोनी के दाहिने कंधे और गर्दन के बीच जा लगी। मौके पर हडकंप मच गया। बितूर थाना प्रभारी प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया कि घायल को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और परिजनों को तहरीर के लिए बुलाया गया है। मौके से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

मॉर्निंग वॉकर को डंपर ने कुचला, स्कूटी को 30 मीटर घसीटा, गुस्साई भीड़ ने किया पथराव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कोहना थानाक्षेत्र में सीएसए जा रहे मॉर्निंग वॉकर को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया और स्कूटी को 30 मीटर तक घसीटा। गुस्साई पब्लिक ने डंपर चालक की पिटाई कर गाड़ी पर पथराव किया। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। कानपुर में कोहना थाना क्षेत्र में गुरुवार को सीएसए जा रहे मॉर्निंग वॉकर को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। इस दौरान भागने के चक्कर में डंपर चालक स्कूटी को 30 मीटर तक घसीटा ले गया। गुस्साई पब्लिक ने चालक की पिटाई कर रोकने की कोशिश की, तो चालक ने गाड़ी भगा दी। लोगों ने आगे जाकर उसे पकड़ लिया और पथराव कर दिया। पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।

मन्त्रीपुरवा निवासी बसंतलाल (57) अंडे का व्यापार करते थे। परिवार में पत्नी मीना व तीन बेटे शिवम, राहुल, अवनीश हैं। बड़े बेटे राहुल ने बताया कि पिता रोज चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। सुबह सात बजे पिता मॉर्निंग वॉक के लिए स्कूटी से निकले थे। बताया कि वीआईपी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने के बाद वह कंपनी बाग चौराहे पर पहुंचे ही थे।



चालक को हिरासत में ले लिया

तभी नवाबगंज थाने के सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने साइड से उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी और कुचलते हुए उनकी स्कूटी को करीब 30 मीटर दूरी तक घसीटा ले गया। वहीं, हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने डंपर पर पथराव शुरू कर दिया। हादसे के बाद कोहना पुलिस ने लोगों को शांत कराकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोहना थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि चालक को हिरासत में ले लिया है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

कोपेस्टेट शिक्षा सदन में छात्रों को निशुल्क किट वितरित

अजय कपूर ने दिया कड़ी मेहनत का संदेश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कोपेस्टेट शिक्षा सदन, दादा नगर में वरिष्ठ भाजपा नेता अजय कपूर ने 332 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री और स्कूल किट वितरित की। उन्होंने छात्रों को डॉ. अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर एकाग्रता से पढ़ाई करने का संदेश दिया।

कानपुर में कोपेस्टेट शिक्षा सदन, जूनियर हाई स्कूल में अध्ययनरत 332 छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कॉपियां, विद्यालय बैग, लंच बाक्स, पानी की बोतल व जूते-मोजे आदि का वितरण मुख्य अतिथि अजय कपूर ने किया। वो विद्यालय समिति के अध्यक्ष भी हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ

चेयरमैन विजय कपूर एवं मुख्य अतिथि ने विद्यालय परिसर में एक-एक फलदार पौधा रोपित कर किया गया। इसके बाद चेयरमैन विजय कपूर ने अंगवस्त्र पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया।

इसके बाद छात्र-छात्राओं को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। चेयरमैन विजय कपूर ने दीपावली के उपलक्ष्य में सभी शिक्षिकाओं को उपहारस्वरूप लेडीज सूट भेंट किए। मुख्य अतिथि ने छात्रों को मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेने और कठिन परिश्रम तथा लगन से अध्ययन करने का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि आपके माता-पिता आपको विद्यालय भेजते हैं और दादा नगर के उद्यमी आपकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था करते हैं। अतः इस अवसर



का सम्मान करते हुए एकाग्रता से पढ़ाई करें और अपने माता-पिता, शिक्षकों तथा समाज का नाम रोशन करें।

कॉपी, किताब, ड्रेस जैसी आवश्यक सामग्री की जाती हैं प्रदान चेयरमैन विजय कपूर ने बताया कि यह विद्यालय कोऑपरेटिव इस्टेट,

दादा नगर द्वारा संचालित है। यहां बच्चों को निशुल्क शिक्षा के साथ-साथ कॉपी, किताब, ड्रेस, स्वेटर, बनियान, जूते-मोजे और टाई-बेल्ट जैसी आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाती है।

साथ ही, विद्यालय में विद्यार्थियों को

दोपहर का निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर बलराम नरुला,, हरीश ईसरानी, दिनेश कुशवाहा, बसंत लाल विश्वकर्मा, आरपी सिंह, सतेंद्र मोहन धीगरा, राजेन्द्र गुप्ता, अनूप कुशवाहा आदि उद्यमी उपस्थित थे।

सीएचसी सरसौल का जच्चा-बच्चा वार्ड बना नर्क, शौचालय का गंदा पानी भरा

प्रसूताएं बाहर लेटी, वीडियो वायरल



स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सरसौल सीएचसी के जच्चा-बच्चा वार्ड में शौचालय का गंदा पानी भर जाने से बद्बू फैल गई, जिससे प्रसूताएं बेड बाहर निकालकर लेटने को मजबूर हुईं। इस अव्यवस्था का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

कानपुर में सरसौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जच्चा-बच्चा कक्ष में शौचालय का गंदा पानी भर गया जिससे पूरे वार्ड में बद्बू फैल गई। प्रसव के बाद आराम कर रही महिलाओं को इतनी परेशानी हुई कि उन्होंने खुद अपने-अपने बेड बाहर निकलवा लिए। तीमारदारों ने इस अव्यवस्था का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर

दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वार्ड के अंदर पानी भरा है और महिलाएं बाहर खुले में लेटी हैं।

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है।

तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में साफ-सफाई की व्यवस्था पहले से ही खराब है, लेकिन इस बार हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए हैं। प्रकरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अविनाश यादव ने बताया वार्ड में किसी मरीज ने शौचालय के अंदर कपड़ा फंसा दिया था उसी की वजह से पानी भर गया था सफाई कर्मी को बुलाकर वार्ड को साफ करवा दिया गया है।

www.swarajindianews.com

उत्तर भारत का तेजी से उभरता...

सांध्यकालीन समाचार पत्र

विज्ञापन एवं सूचनाएं प्रकाशित कराने के लिए सम्पर्क करें:

+91 79851 76100

[swarajindianews](https://www.swarajindianews.com) | [swarajindia_knp](https://www.facebook.com/swarajindia_knp) | [@swarajindianews](https://www.instagram.com/swarajindianews)

एडीजी ने अकबरपुर थाने का दौरा कर साइबर अपराध पर जताई चिंता

» दीपावली से पहले कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए अफसरों को अहम जिम्मेदारियाँ

» मिशन शक्ति अभियान 5.0 और साइबर अपराधों की रोकथाम पर दिए कड़े निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अपर पुलिस महानिदेशक (कानपुर जोन) आलोक सिंह ने थाना अकबरपुर का निरीक्षण करते हुए पुलिस बल को त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय, क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों की उपस्थिति में एक



महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया।

गोष्ठी में एडीजी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा

सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क सक्रिय रखी जाए और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम

आयोजित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि महिलाओं और युवतियों को न केवल कानूनी अधिकारों की जानकारी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं जैसे 1090, 112, 181, 1098, 108, 102 और साइबर हेल्पलाइन 1930/155260 के उपयोग की जानकारी भी दी जाए।

दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस

एडीजी आलोक सिंह ने बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर चिंता जताई और थानों को निर्देश दिया कि जनता को साइबर फॉड से बचाव के लिए जागरूक किया जाए और संदिग्ध मामलों में तत्काल

एफआईआर दर्ज कर जांच तेज की जाए। दीपावली के मद्देनजर उन्होंने आदेश दिए कि बाजारों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई जाए, पटाखों की बिक्री पर सख्त नियंत्रण रखा जाए, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई हो। निरीक्षण के बाद एडीजी ने पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारियों के साथ पैदल गश्त भी की, जिसमें स्थानीय बाजारों और चौराहों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा पैदल गश्त पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करती है और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

पत्नी मायके चली गई, पति झूल गया फांसी के फंदे पर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के अन्तापुर में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय जोगेंद्र के रूप में हुई है। जोगेंद्र ने बीती रात अपने कमरे के अंदर पंखे के कुंडे से गमछे का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने बताया कि जोगेंद्र की पत्नी अंजलि पिछले छह माह से अपने मायके में रह रही थी और उसके वापस न आने पर जोगेंद्र ने यह कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ था और दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। मां राजेश्वरी, पिता मथुरा प्रसाद, भाई आनंद का रो रो कर बुरा हाल था। प्रभारी निरीक्षक संजेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

खेत में ही धान की फसल में निकला अंकुर, किसानों की मेहनत पर पानी फिरा

बारिश से गिर गई पकी फसल, खेतों में हुआ अंकुरण बाजार में नहीं मिल रहा भाव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद क्षेत्र में हुई पिछली मानसूनी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में भरा पानी अब धान की फसल के लिए विनाश का कारण बन गया है। खेतों में खड़ी पकी फसल पानी में गिरकर सड़ने लगी और कई जगहों पर धान के दाने वहीं अंकुरित हो गए। किसान अब इस नुकसान से पूरी तरह हताश हैं।

रसूलाबाद क्षेत्र के बारापुर, बिरहुन, नैनपुर, और कसमढ़ा गांवों में पिछले हफ्ते हुई जोरदार बारिश से खेतों में पानी भर गया। किसानों ने बताया कि जब तक पानी निकला, तब तक पकी हुई धान की बालियां जमीन पर गिर चुकी थीं और उनमें अंकुर फूट आए थे। किसान सुधीर यादव, रामप्रकाश, बृजकिशोर, विनोद यादव (पूर्व प्रधान),



बर्बाद फसल को दिखाता किसान

सुशील व संजय ने बताया कि पूरी सीजन की मेहनत इस बारिश ने चौपट कर दी। धान का दाना सड़ने और अंकुरित होने से अब उसे काटना भी मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि फसल खराब होने के बाद भी बाजार में धान का भाव बेहद कम है। निजी व्यापारी सिर्फ 1700 से 1800

रुपये प्रति क्विंटल तक की दर दे रहे हैं। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दाम मिलने पर किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्षेत्रीय किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि नुकसान का सर्वे कराया जाए और बर्बाद फसल का उचित मुआवजा दिया जाए।

तीन और पांच साल पुराने वादों का चलाया जाएगा निस्तारण अभियान

» राजस्व वसूली में लापरवाही पर डीएम सख्त, अफसरों को दी चेतावनी

» अपात्र को पट्टा मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई: डीएम कपिल सिंह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मां मुक्तेश्वरी देवी समागार में राजस्व और कर-करेतर विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान चलाकर लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को आदेश दिया कि तीन और पांच साल से लंबित न्यायिक वादों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय



समीक्षा बैठक में निर्देश देते डीएम कपिल सिंह

के आदेशों का अनुपालन हर हाल में 15 दिन के भीतर होना चाहिए। यह भी निर्देश दिया कि धारा 67 के कोई भी प्रकरण लंबित न रहें और राजस्व संबंधी प्रत्येक मामले की नियमित समीक्षा की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पट्टा आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति को लाभ न

मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, आईजीआरएस और सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि टीम बनाकर गांवों की ज्वलंत समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), न्यायिक उपजिलाधिकारी, तहसीलदारों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

SIDDHIVINAYAK ENCLAVE
COMMERCIAL GUM RESIDENTIAL



Fully Furnished Flat

- Lift
- Power Backup

For Sale

Ground Floor = Hall (2800sqft.)
1st to 3rd Floor = 3BHK Flat(1550sqft.)

Site Add : Plot No. 600/5, House No. 120/505, Shivji Nagar, Scheme No.1
Kanpur Nagar (Near Shivani Nursing Home)
Near Kanpur Medical Centre Lajpat Nagar, Kanpur
Mob : 9936444099, 7355766844, 9369936943

पति से वीडियो कॉल पर झगड़ा कर नवविवाहिता ने लगाई फांसी

मार्च में किया था प्रेम विवाह, मायके में आकर दे दी अपनी जान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के नौहानौगांव में बुधवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अपने पति से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान हुई कहासुनी के बाद 25 वर्षीय नवविवाहिता ने साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

जानकारी के मुताबिक, नौहानौगांव निवासी रामनरेश गौतम की पुत्री मुस्कान गौतम (25) ने इसी वर्ष मार्च में बदायूं के भद्रौराल निवासी विकी गौतम से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद दोनों के परिवारों ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुस्कान के ससुराल में आए दिन विवाद होते रहे। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष का व्यवहार मुस्कान के प्रति ठीक नहीं था। लगभग 20 दिन पहले वह अपने मायके लौटी थी। बुधवार रात करीब एक बजे मुस्कान अपने कमरे में पति विकी के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई। विवाद इतना बढ़ा कि बात करते-करते मुस्कान ने गुस्से में साड़ी का फंदा बनाकर रोशनदान के



सहारे आत्महत्या कर ली। जब परिजनों ने दरवाजा बंद देखा तो उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हुआ। अंदर झांकने पर मुस्कान का शव फंदे से झूलता देख घर में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर रसूलाबाद थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। साक्ष्य एकत्र किए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पति और ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है।

सपा को अयोध्या का विकास खटक रहा है, आरोपों की साजिश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या नगर निगम अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने सपा के पूर्व मंत्री तेजनाथ पांडेय 'पवन' द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सपा को अयोध्या का विकास खटक रहा है, इसलिए वह साजिश के तहत झूठ फैलाने में लगी है।

महापौर ने कहा कि अयोध्या का तेजी से बदलता चेहरा विपक्ष को असहज कर रहा है। जनता को बरगलाने के लिए यह आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि नगर निगम की स्वच्छ कार्यशैली और पारदर्शी प्रशासन पर सवाल उठाए जा सकें। नगर निगम सभागार तिलक हाल में पत्रकारों से मुखातिब महापौर ने कहा कि ऑडिट आपत्तियाँ एक नियमित प्रक्रिया हैं इन्हें भ्रष्टाचार बताना राजनीतिक अपरिपक्वता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने सभी आपत्तियों का बिंदुवार जवाब तैयार कर लिया है और समय से निस्तारण किया जाएगा।

विकास कार्यों की ऐतिहासिक गति दी

सपा के पूर्व मंत्री के आरोप पर अयोध्या महापौर ने किया तगड़ा पलटवार



सपा के पूर्व मंत्री के आरोपों पर स्वराज इंडिया ने प्रकाशित की थी खबर



पत्रकारों से बातचीत करते महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी

महापौर ने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यसंस्कृति ही नगर निगम की कार्यदिशा है, और इस नीति से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने बीते दो वर्षों में विकास कार्यों की ऐतिहासिक गति दी है चाहे वह सड़क निर्माण हो, दीपोत्सव की व्यवस्थाएं हों या स्मार्ट

सिटी की योजनाएं। सपा इन उपलब्धियों से हताश होकर भातियां फैला रही है। इस मौके पर उपसभापति राजेश गौड़, पूर्व सभापति जय नारायण सिंह रिकू, वरिष्ठ पार्षद बृजेंद्र सिंह, चंदन सिंह, अनिल सिंह, सूर्यकुमार तिवारी सूर्या, अभय श्रीवास्तव, विनय जायसवाल, अजय पांडेय, सलमान हैदर, हरिश्चंद्र गुप्त, तथा पार्षद

प्रतिनिधि रीशू पांडेय सहित बड़ी संख्या में पार्षद उपस्थित रहे। हालांकि पूर्व मंत्री के आरोपों और महापौर के इस सख्त रुख ने अयोध्या की राजनीति में नया ताप भर दिया है। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच नगर निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल और उनके जवाब अब जनता के दरबार में हैं। क्या यह वाकई विकास बनाम विरोध की

यदि किसी स्तर पर झूटि पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पड़ताल जरूरी है, न कि सस्ती राजनीति।
महंत गिरीशपति त्रिपाठी, महापौर अयोध्या

लड़ाई है, या फिर भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शिता का दावा?

बीबीडी ग्रुप की बेनामी संपत्तियों पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई शुरू

» तोराखास की जमीन पर लगा बेनामी संपत्ति जल्ती का बोर्ड, ईडी की कार्रवाई भी संभव



» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बीबीडी ग्रुप की बेनामी संपत्तियों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बेनामी निषेध इकाई (Benami Prohibition Unit) ने चिनहट इलाके के तोराखास गांव में स्थित जमीन पर जल्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। जमीन पर विभाग की ओर से बेनामी संपत्ति होने का बोर्ड भी लगा दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, यह जमीन पहले धर्म सिंह

के नाम पर खरीदी गई थी, लेकिन बाद में इसका रजिस्ट्रेशन मेसर्स विराज इंफाटाउन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दोबारा किया गया। यह कंपनी लखनऊ के पूर्व मेयर और केंद्रीय मंत्री रहे डॉ. अखिलेश दास की पत्नी अलका दास और पुत्र विराज सागर दास की बताई जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, बीबीडी ग्रुप ने धर्म सिंह के नाम से यह जमीन खरीदी थी और बाद में उसे अपनी ही कंपनी, विराज इंफाटाउन, को ट्रांसफर कर दिया।

विभाग के पास ऐसी अनेक बेशकीमती बेनामी संपत्तियों की सूची है जो कथित तौर पर अलका दास और विराज सागर दास के इशारे पर नौकरों, ड्राइवरो, बावर्चियों, माली और अन्य कर्मचारियों के नाम से खरीदी गई हैं।

विभाग की ओर से इन संपत्तियों की गहन जांच पूरी कर ली गई है और अब जप्तीकरण की कार्रवाई औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।

सूत्रों का कहना है कि यह केवल आयकर विभाग की कार्रवाई है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जल्द इस प्रकरण में अपनी एंट्री कर सकता है।

इस कार्रवाई के बाद शहर के रियल एस्टेट जगत में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बीबीडी ग्रुप की संपत्तियों का मूल्य सैकड़ों करोड़ रुपए बताया जा रहा है।

डॉ. दिव्यांश सक्सेना बने इंडियन आयुष एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

बरेली। बरेली के युवा आयुष चिकित्सक डॉ. दिव्यांश सक्सेना को इंडियन आयुष एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह नियुक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनम्र सिंह द्वारा की गई है।

डॉ. दिव्यांश, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वेद प्रकाश सक्सेना कातिब और भाजपा नेत्री किरण सक्सेना के पुत्र हैं। उनकी नियुक्ति से बरेली और कायस्थ समाज में हर्ष की लहर है। डॉ. दिव्यांश के मनोनयन पर डॉ. अरुण कुमार (वन राज्य मंत्री), अधीर सक्सेना (भाजपा महानगर अध्यक्ष), डॉ. विकास वर्मा, डॉ. सुबोध अस्थाना, आलोक प्रधान, श्यामदीप सक्सेना,



मनोज सक्सेना, गोपाल धूप, अश्विनी कमठान, सुनील सक्सेना मिलन, अविनाश सक्सेना, सुधीर मोहन, रवि सक्सेना, रविन्द्र सक्सेना, दीपक राज, विपिन कौसर, शैलेन्द्र सक्सेना शैलू, संजय सक्सेना, अमित सक्सेना बिंदू सहित अनेक गणमान्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

कुमारगंज अस्पताल में दो डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई से मचा हड़कंप

स्वराज इंडिया की खबर का असर



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

अयोध्या। अयोध्या के 100 शैर्या संयुक्त चिकित्सालय, कुमारगंज में फैली अनियमितताओं पर आखिरकार शासन की नजर पड़ी है। स्वराज इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दो चिकित्सकों डॉ. आशा आर्य और डॉ. अरविंद मोर्य के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अयोध्या मंडल को जांच सौंपी है।

डॉ. आशा आर्य पर आरोप है कि वे लंबे समय से अस्पताल में अनुपस्थित रहीं और बार-बार चेतावनी के बावजूद ड्यूटी पर नहीं लौटीं। वहीं डॉ. अरविंद मोर्य पर निजी प्रैक्टिस करने, मरीजों को बाहर की दवाएं लिखने और निजी अस्पताल में रेफर करने के गंभीर आरोप हैं। इसकी शिकायत बीजेपी नेता डॉ० रजनीश सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर भी की

» स्वास्थ्य विभाग की चयनित सख्ती पर उठ रहे सवाल, सीएमएस पर कोई कार्रवाई नहीं

थी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि शासन स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त है। अपर निदेशक डॉ. ब्रजेश चौहान ने भी कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी।

सीएमएस डॉ. रवि पांडेय पर सत्राटा क्यों?

अब यही सवाल अयोध्या से लेकर लखनऊ तक गूंज रहा है। जिस अस्पताल के मुखिया सीएमएस डॉ. रवि पांडेय खुद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने तीन दिन पूर्व एक गर्भवती महिला को यह कहकर लौटा दिया कि रविवार का दिन है, मैं मरीज नहीं

प्रसव पीड़िता तड़पती रही, पर्व पर लिखा डाक्टर इज नॉट एविलेबल



देखता, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ। गंभीर स्थिति में महिला को बिना इलाज रेफर कर दिया गया। परिजन हैरान थे कि एक सरकारी अस्पताल में छुट्टी का बहाना जिंदगी से बड़ा कैसे हो गया? स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर जब हंगामा किया, तब अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले को दबाने की



कोशिश की। लेकिन स्वराज इंडिया की रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदेश भर में यह सवाल उठने लगा कि जब दो डॉक्टरों पर कार्रवाई हो सकती है, तो सीएमएस पर जांच क्यों नहीं?

विभाग की चयनित सख्ती पर उठे सवाल

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, डॉ. पांडेय पर कई शिकायतें पहले भी हो चुकी हैं लेकिन हर बार मामला ऊपर से दबा दिया गया। स्टाफ की जुबान पर अब एक ही वाक्य है। सीएमएस साहब के ऊपर हाथ डालना मना है।

शासन की हालिया कार्रवाई को लेकर यह धारणा मजबूत हो गई है कि यह आधी सख्ती केवल दिखावे के लिए की जा रही है, ताकि जनता का गुस्सा ठंडा पड़े। गांवों से आने वाले मरीज अब खुलकर कह रहे हैं कि कुमारगंज अस्पताल में इलाज नहीं, रविवार वाली राजनीति चल रही है। एक ग्रामीण ने कहा यहां इलाज किसे मिलेगा, यह ऊपर से तय होता है, नीचे तो बस कागज चलते हैं। स्वराज इंडिया की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के भीतर चल रही संरक्षण की राजनीति को उजागर कर दिया।

अजय प्रताप अध्यक्ष, डॉ. आशीष महामंत्री सर्वसम्मति से निर्वाचित

» संयुक्त मोर्चा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अयोध्या के पदाधिकारियों का चयन



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। जिला अस्पताल में बुधवार को कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। राजकीय फार्मासिस्ट महासंघ अयोध्या के अध्यक्ष सत्य प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता व देखरेख में संयुक्त मोर्चा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अयोध्या के पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से

किया गया। इसके बाद उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलायी गई। अजय प्रताप सिंह अध्यक्ष व डॉ. आशीष श्रीवास्तव महामंत्री निर्वाचित हुए।

यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों-अधिकारियों के समस्याओं के त्वरित निदान के लिये संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है।

सह संयोजक, संजीव गुप्ता व अनिल सिंह उपमंत्री, संदीप सिंह व अरविन्द दूबे संयुक्त मंत्री, आरबी सिंह संगठन, ओमप्रकाश तिवारी कोषाध्यक्ष, अनय दूबे सम्प्रेक्षक, प्रभाशंकर द्विवेदी संयोजक व सत्यप्रकाश चौधरी संरक्षक की भूमिका में रहेंगे।

रुदौली से हटाए गए एसडीएम विकास धर दुबे

» सोहावल के न्यायिक एसडीएम पद पर की गई नई नियुक्ति

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या प्रशासनिक हलकों में फिर एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अपनी संवेदनशील कार्यशैली के लिए चर्चित एसडीएम विकास धर दुबे को रुदौली से स्थानांतरित कर सोहावल का न्यायिक एसडीएम बनाया गया है। यह आदेश उनके दो दिन के अवकाश पर राधा रानी के दर्शन से लौटने के दौरान मिला।

अप्रैल 2025 में विकास धर दुबे को अयोध्या सदर से बीकापुर का एसडीएम बनाया गया। इस दौरान उन्होंने गरीबों की मदद और अवैध खनन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। स्थानीय लोगों में उनकी छवि जनता के अफसर के रूप में बनी। जुलाई 2025 में बीकापुर से अचानक तबादले पर अधिवक्ताओं और नागरिकों ने विरोध जताया। कहा गया कि ऐसे अफसर की जरूरत सिस्टम को है, न कि सजा। अगस्त 2025 में फिर उन्हें रुदौली तहसील का एसडीएम नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार और खनन माफिया



पर लगाम कसी। गरीबों के पक्ष में उनके आदेशों ने जनता में भरोसा जगाया। सितंबर 2025-विधायक से कथित विवाद को लेकर उन्हें निशाने पर लिया गया। लेकिन दुबे ने आरोपों को निराधार और राजनीतिक प्रेरित बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। अक्टूबर 2025- राधा रानी के दर्शन के लिए दो दिन के अवकाश पर गए दुबे जब लौट रहे थे, तभी उन्हें स्थानांतरण पत्र मिला। जिसमें उन्हें सोहावल के न्यायिक एसडीएम के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई।

दानापुर में यूपी सीएम की हुंकार, विपक्षियों को जमकर सुनाई खरी-खरी कांग्रेस-आरजेडी के एजेंडे में विकास की जगह परिवार कल्याण है: योगी

कहा- आज बिहार में विकास भी है और विरासत भी है, जनता आस्था का सम्मान करने वाली एनडीए के साथ

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया न्यूज।

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर के बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन में पटना पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल और उनकी सहयोगी पार्टियां बिहार में विकास बनाम बुर्के की शरणावली कर रहे हैं। बिना पहचान बताए घुसपैठियों से वोट लेकर यहां के मूल नागरिकों के अधिकार की चोरी करना चाहते हैं। लेकिन यह अब नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाई पर पहुंचेगा।

योगी ने कहा कि जब बिहार के नागरिक विकास की बात करना चाहते हैं तो राजद, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने बुर्के पर बहस शुरू कर दी है। इन दलों के नेता फर्जी पोलिंग के पक्ष में हैं जो लोकतंत्र के लिए बड़ी



मिशन बिहार

चुनौती है। बिहार के नौजवान जब अपनी प्रतिभा के दम पर विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो राजद और कांग्रेस बुर्के पर बहस की पहल का कुत्सित प्रयास कर रही है। विदेशी घुसपैठियों से बुर्के की आड़ में फर्जी पोलिंग कराना चाहते हैं। यह बिहारवासियों के हक की डकैती होगी जिसे कभी



होने नहीं दिया जाएगा। जब हर मतदाता पहचान पत्र से अपनी पहचान करवाकर वोट डालने की बात करता है तो बुर्के में पहचान छिपाकर वोट डालने की बात करना सही नहीं है। चुनाव आयोग जब मजबूती से इस दिशा में बढ़ रहा है तो ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुनिया के किसी कोने में जाने पर पहचान और

चेहरा दिखाना पड़ता है तो वोट में क्या दिक्कत है। ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा दिखाए जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं ताकि पहले की तरह वोट लूट सकें।

योगी ने कहा कि 1990 के बिहार के बिहार को याद कीजिए जब जंगलराज और

संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी अर्पित की श्रद्धांजलि



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लखनऊ स्थित शिव शांति आश्रम पहुंचे और आश्रम के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संत शिरोमणि के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपस्थित शोकाकुल श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के पार्थिव शरीर पर केसरिया अंग वस्त्र ओढ़ाया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। गौरतलब है कि संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी बुधवार को ब्रह्मलीन हो गए थे।

परिवारवाद में बिहार के तबाह कर दिया गया। आपने देखा होगा हमारे बिहार की ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बनाकर रख दिया। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया। विकास के नाम पर कैसे अराजकता फैलाई गई यह किसी से छुपा नहीं है। विकास के नाम पर अपराधी और माफिया को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच दिया गया।

यूपी: 2027 फतेह के लिए मायावती की रणनीति रेडी

बसपा सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं को बैठक में दिए निर्देश



» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। बसपा प्रमुख ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हालांकि, उनके मतीजे आकाश आनंद खराब स्वास्थ्य के कारण इसमें शामिल नहीं हो सके। चुनावी रणनीति और पांचवीं बार सरकार बनाने की कोशिश के चलते मायावती ने ये बैठक बुलाई। इस दौरान, मायावती ने पार्टी नेताओं का चुनावी तैयारियों पर मार्गदर्शन किया और उत्तर प्रदेश में बसपा को पांचवां कार्यकाल दिलाने की रणनीति की रूपरेखा पर चर्चा की। मुख्य चर्चा आगामी चुनावों के प्रति पार्टी के दृष्टिकोण पर केंद्रित रही।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए की बूथ स्तर तक संगठन के गठन का काम

मिशन बिहार: पार्टी ने 88 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 40 दिग्गज करेंगे प्रचार

बसपा सुप्रीमो ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को बसपा ने 88 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इसके साथ ही 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की गयी है। बसपा ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और युवा उम्मीदवारों को तरजीह दी है। इस बार बसपा ने कुछ सीटों पर जमीनी कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया है, ताकि संगठन को मजबूती मिल सके और जनता के बीच पकड़ गहरी हो। वहीं, बसपा की स्टार प्रचारक सूची में मायावती, राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के साथ ही कई वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और संगठन के प्रमुख चेहरे शामिल किए गए हैं।

की सरकार रही है उस समय सरकार ने जो काम किए वह जन-जन तक पहुंचाए जाएं। अपनी जमीनी रणनीति के अलावा, बसपा अपनी भाईचारा समितियों के जरिए मुसलमानों, ओबीसी, दलितों और ब्राह्मणों सहित विभिन्न समुदायों का समर्थन मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

कौशांबी: मुस्लिम फैमिली ने अपना लिया हिंदू धर्म

मेहंदी अली से अनुज और सायमा से बनी सौम्या



» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

कौशांबी। यूपी में एक और मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया है। कौशांबी के सरायअकिल के पुरख्वास निवासी मेहंदी अली ने पूरे परिवार के साथ दुर्गा मंदिर में पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच सनातन धर्म अपना लिया। इस मौके पर हिंदू रक्षा समिति के अलावा अन्य कई लोग मौजूद रहे। पुरख्वास निवासी मेहंदी अली हिंदू धर्म में पूरी आस्था रखते थे। सनातनी विचारधारा उन्हें रास आ रही थी। मेहंदी अली ने परिवार समेत मेहंदी अली ने मंझनपुर के दुर्गा मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया। अब मेहंदी अली अनुज प्रताप सिंह के नाम से जाने जाएंगे। उनकी पत्नी सायमा अब सौम्या अनुज सिंह और बेटी उर्वा अब उर्विजा अनुज सिंह के नाम से जानी जाएगी। तीनों ने हिंदू धर्म की दीक्षा ले ली है।

पूरी दुनिया को एक परिवार मानने वाली यह विचारधारा हमें एकजुट होने की प्रेरणा देती है। वर्षों से हम इसकी ओर आकर्षित थे

और आज आखिरकार वैदिक मंत्रों के बीच सनातन का आश्रय ले लिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय परिवार की आपसी सहमति से लिया गया है और अब वे हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करेंगे। अनुज प्रताप सिंह वन अंब्रेला चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय है। ट्रस्ट के माध्यम से वे वृक्षारोपण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर हिंदू रक्षा समिति के वेद प्रताश सत्याश्री, दीपक मोर्य, शिवम पांडेय, भुवनेश्वर तावरी, विपिन यादव, हर्षित मिश्रा, आशीष कुमार, उमेश गुप्ता, अजय सिंह आदि लोगों ने अनुज प्रताप सिंह मौजूद रहे। मेहंदी अली पहले से ही हिंदू थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। उनको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने घर वापसी की ठानी। मेहंदी अली ने न कि खुद सनातन धर्म अपनाया बल्कि बीवी और बच्ची को भी सनातन की दीक्षा दिलाई।